भारत में कार्यरत पत्रकारों के लिये उनके अधिकारों से संबंधित मार्गदर्शिका

13 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में टेलीविजन पत्रकार भारतीय संसद के परिसर से पत्रकारिता करते हुए। रॉयटर्स /अदनान आबिदी

THOMSON REUTERS FOUNDATION
TrustLaw
CPJ Committee to Protect Journalists
Shardul Amarchand Mangaldas

मुंबई, भारत में 8 नवंबर, 2016 को एक संस्थान के निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा पत्रकारों पर किये गये हमले के विरोध में एक पत्रकार अपने मुंह में चेन और ताला लगाये हुए। रॉयटर्स/दानिश सिद्दीकी

प्रस्तावना

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने वर्ष 2015 से, विभिन्न विधानों / कानूनों के तहत भारत में पत्रकारों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए आधार सामग्री एवं आँकड़ों का निरीक्षण एवं अवलोकन किया है। इनमें से कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 शामिल हैं। सीपीजे ने कोविड -19 (COVID-19) महामारी पर समाचार संकलन एवं पत्रकारिता करते समय पत्रकारों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत दर्ज किए गए मामलों की सारिणी बनायी गयी है। इस मार्गदर्शिका की रचना पत्रकारों के लिए एक संसाधन के रूप में की गई है, जो एक आवश्यक सेवा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उनकी भूमिका के आलोक में समाचार लेखन या समाचार प्रेषण करते समय उनके अधिकारों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह मार्गदर्शिका पत्रकारों को दंडात्मक कानूनों पर मार्गदर्शन देने के लिए भी है, जिनका उपयोग उनके खिलाफ गिरफ्तारी, मुकदमों या ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए किया जा सकता है।

सीपीजे, इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में नि:शुल्क कानूनी समर्थन प्रदान करने के लिए शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के विद्वान अधिवक्ताओं का और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की नि:शुल्क कानूनी सेवा ट्रस्टलॉ का इस अभिप्राय के निमित्त नि:शुल्क संयोजन की सुविधा देने और इसकी योजना का समर्थन करने के लिए आभारी है। इसका उद्देश्य भारत में अपने अधिकारों और उपायों को समझने की मांग करने वाले पत्रकारों एवं समाचार संस्थानों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल, व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

श्रीनगर में 10 जनवरी, 2020 को सरकार द्वारा संचालित मीडिया केंद्र के अंदर काम करने के दौरान इंटरनेट का उपयोग करते हुए पत्रकार। रॉयटर्स/दानिश इस्माइल/फाइल फोटो

विषयसूची

एक संक्षिप्त विवरण 4

अध्याय I:
पत्रकारों के अधिकार - मुक्त भाषण की मौलिक अवधारणाएँ 8

अध्याय II:
कानून के तहत नामजद किया जाना 9

अध्याय III:
सही साधन/उपाश्रय प्राप्त करना 12

अध्याय IV:
अचानक कई मुकदमों में नामजद कर दिया जाना 15

अध्याय V:
ऑनलाइन दुर्व्यवहार का मुकाबला करना 17

अध्याय VI:
कोविड 19 (COVID-19) से संबंधित पत्रकारिता 21

नई दिल्ली, भारत में 6 सितंबर, 2017 को भारत की एक वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश के सम्मान में तख्तियां और मोमबत्तियां थामे हुए लोग, जिनकी पुलिस के अनुसार मंगलवार को उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी थी। रॉयटर्स/अदनान आबिदी

संक्षिप्त विवरण

इस व्यापक मार्गदर्शिका का उद्देश्य पत्रकारों को भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध अधिकारों, उपचारों और सुरक्षा उपायों की कामकाजी समझ से लैस करना है। आपके लिए याद रखने लायक कुछ प्रमुख बिन्दु:

भारत में एक पत्रकार के रूप में आपके क्या अधिकार हैं?

- मुक्त भाषण का अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रसार और पूर्व-सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार भी शामिल हैं।
- इसका अर्थ है कि आप सरकार या देश की आलोचना कर सकते हैं।
- हालांकि, यह यह मुक्त भाषण की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, और यदि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है, अपराध करने के लिए उकसाती है, या इससे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो आपके भाषण को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

आपराधिक कार्रवाई का सामना करना और निवारण प्राप्त करना

कहां से शुरू करें

- अपने वकील के माध्यम से जानकारी लें कि क्या आपके खिलाफ कोई पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।
- स्पष्ट सूचना प्राप्त करें कि आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए किस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- पत्रकारों को फंसाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनों में क्रमशः मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, राजद्रोह, आपराधिक साजिश, सार्वजनिक उपद्रव या दंगे भड़काने के लिए 1860 शामिल हैं; न्यायालयों की अवमानना अधिनियम- 1881, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 हैं।
- जानकारी प्राप्त करें कि आप पर प्रकार की आपराधिक गतिविधियों या अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है (अर्थात, कौन सा कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि भारतीय दंड संहिता, आदि), और आपके खिलाफ की गयी शिकायत से संबंधित शिकायत पत्र को प्राप्त करने का अनुरोध करें।
- अपने वकील/अधिवक्ता से शिकायत को रद्द करने के सन्दर्भ में आपकी मदद करने के लिए कहें (अधिक विवरण के लिए अध्याय III देखें)।

गिरफ्तारी पर आपके अधिकार

- इस तथ्य की जांच करें कि क्या आपको गिरफ्तार करने और आपके निवास या कार्यालय में छापा मारने के माध्यम से किसी सामान या सामान की तलाशी लेने या किसी भी सामान को जब्त करने का कोई वारंट है- इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच होना उन्हें देखना समझना नियंत्रित करना भी शामिल है। यदि आपको ऐसे किसी साक्ष्य को प्रकट करने के लिए विवश किया जा रहा है तो अपने वकील से परामर्श करें।
- गिरफ़्तारी के समय, पुलिस को आपको गिरफ़्तारी के क़ानूनी प्रावधानों और ज़मानत से संबंधित आपके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए एक वारंट की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर जमानती होते हैं, जबकि गैर-जमानती संज्ञेय अपराधों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है (दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची संख्या (I) देखें)
- अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आप जमानत मांग सकते हैं और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को सूचित कर सकते हैं।
- अपनी पसंद का वकील नियुक्त करना और पूछताछ के दौरान उन्हें उपस्थित रखना आपका मौलिक अधिकार है।
- यदि आपकी किसी वकील तक पहुंच नहीं है, तो आप राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
- आपको पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार है यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने से आप पर दोष लग सकता है।
- गिरफ्तारी करते समय, पुलिस अधिकारी को एक "गिरफ्तारी का ज्ञापन" तैयार करना चाहिए जिस पर आपके और आपके किसी रिश्तेदार/पड़ोसी के प्रतिहस्ताक्षर हों।
- इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आपके द्वारा नामित व्यक्ति को आपके ठिकाने का विवरण प्रदान करना चाहिए और उसे रिकॉर्ड करना चाहिए।
- महिलाओं को पुरुष अधिकारियों द्वारा केवल दिन के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है; अगर आपको सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है तो घटनास्थल पर एक महिला पुलिस अधिकारी को उपस्थित होना चाहिए।
- आप अपनी गिरफ़्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपने जनपद के सत्र न्यायालय या अपने राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का जवाब देना और इसे कैसे रद्द करवाया जाए

- यहाँ रद्द करने का अर्थ केवल प्राथमिकी को रद्द करना, काट देना या खारिज करना है।
- अपने वकील से अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका माननीय उच्चतम न्यायलय या अपने राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में दायर करने में मदद करने के लिये कहें।
- अदालतें उन एफआईआर को रद्द कर देती हैं जो केवल अभियुक्तों को परेशान करने और बदनाम करने के लिए बिना किसी वास्तविक अपराध के दायर की गई प्रतीत होती हैं।
- एक वकील के माध्यम से, आप बुरे इरादे से या दुर्भावना से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने खिलाफ मामला खत्म करने की मांग कर सकते हैं। (अतिरिक्त जानकारी अध्याय (III) में प्राप्त करें)

यदि आपको हिरासत में ले लिया जाता है तो क्या करें

- अगर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, तो आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

क्या होगा यदि आपको 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाए?

- यदि आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे की निर्धारित अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, या यदि आपको सप्ताहांत के दौरान गिरफ्तार किया जाता है या यदि पुलिस के रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है और किसी भी तरह से जो एक गलत हिरासत की ओर ले जाता है, ऐसी किसी भी परिस्थिती में आपके वकील पुलिस को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।
- अगर आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता है, तो आपके वकील बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह अदालत से पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका है।
- साथ ही अगर आपको गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में आप अपने वकील के माध्यम से धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र भी समक्ष अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (उप जिलाधिकारी) या संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक

मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

- ऐसी याचिका सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।
- अदालतें इस तरह का आदेश दे सकती हैं यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया है, या बिना कोई अपराध किए गिरफ्तार किया गया है, या गलत इरादे से गिरफ्तार किया गया है।

अदालतें गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठा सकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे सकती हैं।

जागरूक होने के लिए अन्य युक्तियाँ एवं अधिकार

- यदि आपने पुलिस हिरासत में हिंसा का सामना किया है तो आप न्यायालय से चिकित्सीय परीक्षण की मांग कर सकते हैं।
- जमानती अपराधों के लिए, आपके वकील अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना, आपकी ओर से सीधे पुलिस के पास जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।
- किसी पुलिस अधिकारी से पूछे जाने पर अपना नाम और पता साझा करने से इंकार न करें क्योंकि यह गिरफ्तारी का आधार हो सकता है। हालाँकि, आपको इस आधार पर 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
- पुलिस से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट करते समय या पुलिस के साथ बातचीत करते समय, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा बिना वारंट के गिरफ्तारी का आधार है। पुलिस के साथ किसी असहयोग को शामिल करने के लिए इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको पूछताछ के लिए उपस्थिति का नोटिस देता है, तो यह सलाह दी जाती है कि आप उसका पालन करें (अपने वकील के साथ)। यदि आप पुलिस के साथ सहयोग करते हैं तो मजिस्ट्रेट ज़मानत देने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं।

यदि आप पर मुकदमा कायम किया जा रहा है तो क्या करें

एक मुकदमे के लिये आधारों की पहचान करें

- एक सिविल वाद या मुक़दमा, सिविल मानहानि के लिए सबसे अधिक संभावना।
- आपराधिक मानहानि का एक आपराधिक मामला - जिसमें प्राथमिकी और गिरफ्तारी शामिल है।

नई दिल्ली, भारत में 29 जुलाई, 2015 को एक टेलीविजन पत्रकार बारिश के बीच सर्वोच्च न्यायालय के परिसर से पत्रकारिता करते हुए। रॉयटर्स/अनिंदितो मुखर्जी

- एक वकील की सहायता प्राप्त करें और उपलब्ध बचाव के तरीकों पर विचार करें (जैसे कि मानहानि के दावों के खिलाफ)। यदि आप एक वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो आप मुफ्त कानूनी सहायता लेने पर विचार कर सकते हैं (कृपया इस बारे में अधिक जानकारी के लिए इस मार्गदर्शिका के अध्याय (III) का संदर्भ लें)।
- ऐसे मुकदमों से निपटने के लिए मार्गदर्शिका का अध्याय (IV) देखें

दीवानी मुकदमों के प्रकार

- दीवानी वादों में दीवानी मानहानि, मानहानि और/या आपके काम के प्रकाशन को रोकने वाले निषेधाज्ञा के मामले शामिल हो सकते हैं।
- अक्सर वादी चाहते हैं कि आप नुकसान की भरपाई करें, प्रकाशित कार्य वापस लें, सार्वजनिक माफी जारी करें, सुधारात्मक बयान जारी करें या आपराधिक मानहानि के लिए दंडित हों।
- यदि आपका दावा सत्य है और जनहित में किया गया है, तो आप कानून द्वारा संरक्षित हैं।
- आपको अपने वकील से जवाब देने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार से कैसे निपटें

- आप जिस ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं, उनमें धमकी मिलना , डराना-धमकाना, साइबरस्टॉकिंग, डॉक्सिंग, प्रतिरूपण, ट्रोलिंग, साइबर चोरी, रिवेंज पोर्न, मानहानि और स्पैमिंग शामिल हैं।
- आपकी शिकायत दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है और यदि वे ऐसा करने से मना करते हैं, तो आप पुलिस अधीक्षक या संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को डाक द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
- टीआरफिल्टर का उपयोग करें, जो एक उपकरण है जिसका उपयोग संगठन अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
- अध्याय (V) में और जानकारी प्राप्त करें।

COVID-19 महामारी के बारे में कैसे पत्रकारिता करें

- महामारी पर रिपोर्ट करते समय प्रामाणिक और सत्यापित स्रोतों पर भरोसा करें।
- राज्य-विशिष्ट कानूनों का ध्यान रखें जिनका आपको पालन करना पड़ सकता है और महामारी पर रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ सकती है।
- COVID-19 पर रिपोर्टिंग के लिए स्थापित किए गए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से अवगत रहें।
- महामारी पर अपनी रिपोर्ट में सत्यापित स्रोतों को शामिल करें।
- नकली समाचार फैलाने से सावधान रहें क्योंकि इससे उकसाने वाली कार्रवाई के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे मानहानि, बदनामी, मानहानि, दंगा भड़काना और/या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा आदि।

26 दिसंबर, 2019 को पुलिस की बर्बरता और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ भारत के मुंबई शहर में एक विरोध प्रदर्शन जुलूस के दौरान मोमबत्तियाँ और तख्तियां थामे हुए पत्रकार। रॉयटर्स / फ्रांसिस मैस्करेन्हेस

अध्याय (I): पत्रकारों के अधिकार

मुक्त भाषण की मौलिक अवधारणाएँ

भारत का संविधान अनुच्छेद 19 (1) के तहत मुक्त भाषण के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ में विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल करने के लिए की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जनहित के नाम पर प्रेस की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत ने असंवैधानिक रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशन स्थान की सीमाओं और प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने के अन्य अप्रत्यक्ष साधनों को भी समाप्त कर दिया है। एक पत्रकार के रूप में, आपके लिए भारतीय संविधान के तहत उन स्वतंत्रताओं को समझना महत्वपूर्ण है, जिनके आप और आपका संगठन हकदार हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रसार की स्वतंत्रता और पूर्व-सेंसरशिप के विरुद्ध स्वतंत्रता शामिल है। न्यायालयों ने इन बातों को रद्द कर दिया है: समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या और आकार नियंत्रण, कुछ प्रकार की समाचार सामग्री के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकताएं, और समाचार पत्रों में विज्ञापन या व्यावसायिक भाषण पर सीमाएं।

सूचना देने और प्राप्त करने के अधिकार को भी मुक्त भाषण के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये स्वतंत्रताएं अनियंत्रित नहीं हैं, और सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध करने के लिए उकसाने आदि जैसे बहुत सीमित आधारों पर ही "उचित" सीमा तक सीमित हो सकती हैं, जैसा कि अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रदान किया गया है। इस तरह के प्रतिबंधों की "तर्कसंगतता" न्यायपालिका द्वारा किसी दिए गए मामले के तथ्यों की जांच पर और न्यायिक मिसाल के आलोक में निर्धारित की जाती है जो ऐसे तथ्यों पर लागू हो सकती है। इस संबंध में अदालतों द्वारा समर्थित अभिव्यक्ति की आज़ादी के कुछ सिद्धांत, जो पत्रकारों के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:

- सरकार की नीतियों की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है;
- देश के बारे में बुरा प्रचार संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है;
- विवादित भाषण को प्रतिबंधित किया जाना सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान या अपराध के लिए उकसाने का निकटतम कारण होना चाहिए, जिस आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है, न कि कोई दूरस्थ कारण; और
- संवैधानिक रूप से प्रत्याभूत स्वतंत्रता को केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब कानून की गड़बड़ी, या हिंसा के लिए उकसाने का आसन्न खतरा हो।

22 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के परिसर के बाहर दिखाई देते टेलीविजन पत्रकार। रॉयटर्स/अनुश्री फडणवीस/फाइल फोटो

अध्याय (II): कानून के तहत नामजद किया जाना

भारत में, पत्रकारों को संभावित रूप से लक्षित करने के लिए कई प्रकार के कानूनों का उपयोग किया गया है, जिनमें ऐसे कानून भी शामिल हैं जो यकीनन पत्रकारिता के विनियमन (जैसे मानहानि कानून) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत हैं। इसलिए आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप पर किन अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है, ताकि आप उचित उपाय और उपचार की तलाश कर सकें, भले ही आपके खिलाफ लगे आरोप किसी भी कानून के तहत दूर की कौड़ी लगें।

भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") भारत में प्राथमिक आपराधिक कानून संविधि है। पत्रकारों के खिलाफ ज्यादातर मामले आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज किए जाते हैं। इस अध्याय में वर्णित कई प्रकार के व्यष्टि अध्ययन उन उदाहरणों को उजागर करते हैं जहां पत्रकारों को दंडित करने के लिए आईपीसी के सबसे सामान्य प्रावधानों का उपयोग किया गया है।

आपराधिक मानहानि (धारा 499) किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के लिए दंड।	गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, जय शाह ने एक ऑनलाइन समाचार प्रकाशन, द वायर के संपादकों एवं एक पत्रकार पर एक लेख प्रकाशित करने के लिए मानहानि का आरोप लगाया, उक्त लेख में जय शाह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गलत तरीके से व्यावसायिक लाभ कमाया था। द वायर ने मानहानि के मामले को रद्द करने के लिए अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया, और इसके बजाय परीक्षण के दौरान लेख में दिए गए बयानों को सही ठहराने का अवसर लिया।
लोकसेवक के आदेश की अवहेलना (धारा 188) किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना करना एक दंडनीय अपराध है, अगर इस तरह की अवज्ञा के परिणामस्वरूप झुंझलाहट हो सकती है या जोखिम हो सकता है, चोट लगने से काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है या दंगा हो सकता है।	हिमाचल प्रदेश में हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल में कार्यरत एक पत्रकार ओम शर्मा पर तीन अन्य आरोपों के साथ लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था। COVID-19 लॉकडाउन के कारण भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ प्रवासी श्रमिकों द्वारा सड़क के किनारे विरोध प्रदर्शन से संबंधित समाचार संकलन एवं प्रकाशन करने के बाद उन पर आरोप लगाया गया था। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में उसके खिलाफ तीन मामलों में जांच शुरू की गई थी।
अश्लीलता (धारा 292) किसी भी दृश्य, सचित्र, या मौखिक अभ्यावेदन या चित्रण को बेचना, प्रदर्शित करना, वितरित करना आदि जिनका दर्शकों के मन- मस्तिष्क में दुराचार या भ्रष्टाचार का कारण बनने की संभावना है, एक दंडनीय अपराध है।	2016 में, बस्तर में एक पत्रकार पर अश्लीलता के लिए आरोप लगाया गया और गिरफ्तार किया गया, जब उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर पत्रकारों की स्वतंत्रता से डरते हुए पुलिस अधिकारियों की आलोचना की। उक्त पत्रकार को उसी वर्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना (धारा 295ए) किसी भी लिखित या मौखिक बयान या अन्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से उस समुदाय की धार्मिक मान्यताओं का जानबूझकर अपमान करके किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना।	पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और उनके साथ अन्य लोगों को धर्म के आधार पर सांप्रदायिक शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रावधानों के तहत तब गिरफ्तार किया गया था, जब वे वर्ष 2020 में कथित सामूहिक बलात्कार और एक दलित महिला की मौत के बाद रिपोर्ट करने के लिए हाथरस गए थे। 2022 में उनकी गिरफ्तारी के 23 महीने बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत जमानत दे दी।

देशद्रोह (धारा 124ए) कोई भी मौखिक या लिखित बयान देना जो भारतीय राज्य और सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या असंतोष की भावनाओं को जगा सकता है।	भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा COVID संकट से निपटने के लिए भारत सरकार की आलोचना करने वाली समाचार रिपोर्ट सरकार के खिलाफ हिंसा भड़का सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया और कहा कि "सरकार की क्रूर आलोचना करना भी एक पत्रकार के स्वतंत्र भाषण के अधिकार के भीतर माना जायेगा।"
सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान (धारा 505) ऐसे किसी भी बयान या अफवाह को बनाना या प्रकाशित करना या प्रसारित करना अपराध है जो निम्नलिखित को भड़का सकती हैं: • विद्रोह में शामिल होने के लिए सशस्त्र बलों का एक सदस्य; या • जनता में डर या अलार्म और इस प्रकार राज्य के खिलाफ अपराध; या • किसी वर्ग या समुदाय का दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करना; या • धर्म, जाति और अन्य आधारों पर समुदायों के बीच घृणा या दुश्मनी को जन्म देना।	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेमी होने का दावा करने वाली एक महिला के बारे में एक ट्विटर पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ इस आधार पर एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी कि वह अफवाहें फैला रहे थे और उनके द्वारा सोशल मीडिया पर की गयी पोस्ट "अश्लील" थी। जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, न्यायालय ने इस बात की चेतावनी भी दी कि इस आदेश को उनके ट्विटर पोस्ट के अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

विश्वेश्वर भट के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित अवधारणा

जबकि उपरोक्त तालिका पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधानों पर चर्चा करती है, यह मामला इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि पत्रकारों पर मुकदमा चलाने के लिए आईपीसी के असंभावित प्रावधानों का भी उपयोग कैसे किया जा सकता है।

एक कन्नड़ दैनिक के प्रकाशक विश्वेश्वर भट के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी ने अपने दादा, पूर्व प्रधान मंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के साथ शराब के नशे में विवाद किया था। भट पर न केवल मानहानि का आरोप लगाया गया था, बल्कि जालसाजी और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया था, जो कि आर्थिक अपराध हैं।

उपरोक्त उदाहरण के साथ, इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्रकारों के खिलाफ आईपीसी के कुछ अन्य प्रावधानों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आपराधिक साजिश (धारा 120 बी)

यह अपराध दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित है जो अवैध कार्य या अवैध तरीकों से कानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। उदाहरण के लिए, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए साथी पत्रकारों के साथ एक बड़ी आपराधिक साजिश में भाग लेने का भी आरोप लगाया गया है।

दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना (धारा 336))

उतावलेपन या लापरवाही वाले कार्यों में शामिल होना जो दूसरों के जीवन या उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, भी एक दंडनीय अपराध है। इस प्रावधान का इस्तेमाल COVID-19 संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ किया गया था।

लापरवाही वाले कार्य से खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना (धारा 269)

इस जानकारी के साथ लापरवाही से या अवैध रूप से कोई भी कार्य करना कि इस तरह के कार्य से संक्रमण या खतरनाक बीमारी फैल सकती है, एक अन्य प्रावधान है जिसे पत्रकारों को फंसाने के लिए महामारी के दौरान लागू किया जा रहा है।

लोक उपद्रव (धारा 268)

ऐसा कोई भी कार्य जो सार्वजनिक उपद्रव, चोट, खतरे, या जनता या लोगों को परेशान करने या किसी भी सार्वजनिक अधिकारों के प्रयोग में हो सकता है।

लोक सेवक को उसके कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा डालना (धारा 186)

यह एक और प्रावधान है जिसका दुरुपयोग उन पत्रकारों के खिलाफ किया गया है जो किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की आलोचना करते हैं।

राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना (धारा 124ए))

यह अपराध सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह में भाग लेने पर जोर देता है। फिर भी, सरकार पर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है।

पत्रकारों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के अलावा भी कुछ कानून हैं। हाल की कुछ घटनाओं पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

संविधि	चित्रण
न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1881 यह कानून उन प्रकाशनों को दंडित करता है जो दर्शकों/पाठकों के मन में न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ या उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं या उन्हें बदनाम कर सकते हैं।	मेघालय उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस.आर.सेन द्वारा दिए गए निर्णयों की आलोचना करने वाले एक लेख को प्रकाशित करने के लिए शिलांग टाइम्स की प्रकाशक और संपादक पेट्रीसिया मुखिम पर अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत 200,000 रुपये का जुर्माना लगाया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में मेघालय उच्च न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा।
आपदा प्रबंधन अधिनियम ("डीएमए"), 2005 डीएमए स्वास्थ्य संकट सहित प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। किसी आपदा या उसकी गंभीरता के बारे में कोई झूठी चेतावनी या चेतावनी देना अपराध है, साथ ही किसी आपदा के समय किसी राहत, मरम्मत या लाभ के बारे में झूठे दावे करना भी अपराध है।	COVID-19 के दौरान झूठी खबरों का जवाब देने और महामारी के लिए सरकारी प्रतिक्रियाओं की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर हमला करने के लिए डीएमए के प्रावधानों को लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, पत्रकार अश्विनी सैनी के खिलाफ उनकी समाचार रिपोर्ट के लिए एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश में जिले के सुंदरनगर उप-मंडल में फंसे प्रवासी श्रमिकों को राशन की आपूर्ति करने में मंडी जिला प्रशासन की विफलता को उजागर किया गया था।
महामारी रोग अधिनियम (ईडीए), 1897 यह एक क़ानून है जो सरकार को एक महामारी के प्रकोप को संबोधित करने और रोकने के लिए कोई विशेष नियम या विनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। ईडीए के तहत ऐसे नियमों या विनियमों का उल्लंघन आईपीसी के तहत एक लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा के समान सजा का वारंट कर सकता है।	महामारी के दौरान पत्रकारों को दंडित करने के लिए डीएमए की तरह, यह कानून भी राज्य के हाथों में एक अतिरिक्त उपकरण बन गया था। महामारी से संबंधित खाद्य वितरण प्रयासों में बड़े पैमाने पर सरकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक समाचार रिपोर्ट के लिए कोयम्बटूर में एंड्रयू सैम पांडियन के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। कोयंबटूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस की कड़ी आपत्ति के बावजूद उनकी जमानत के पक्ष में आदेश दिया था।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") यह क़ानून साइबर-अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना और सामग्रियों को साझा करने से संबंधित है।	बस्तर में एक पत्रकार से जुड़े एक मामले में आईटी अधिनियम लागू किया गया था, पत्रकार ने व्हाट्सएप ग्रुप पर कथित रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित की थी। डिजिटल मीडिया के विस्तार के साथ, पत्रकारों को और दंडित करने के लिए आईटी अधिनियम के प्रावधानों को तेजी से लागू किया जा रहा है।
गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 ("यूएपीए") यह आतंकवादी गतिविधियों की जांच और आतंकवाद के लिए वित्त पोषण के लिए एक कड़ा कानून है	मसरत ज़हरा, जम्मू और कश्मीर में कार्यरत एक स्वतंत्र फोटो पत्रकार पर यूएपीए के तहत सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट के लिए आरोप लगाया गया था, जहां उन्होंने अक्सर अपनी पत्रकारिता से संबंधित तस्वीरें चस्पा की थीं। इस विशेष उदाहरण में, मसरत ने दिसंबर 2019 में एक महिला से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट के लिए ली गई कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनके पति को कथित तौर पर भारतीय सेना द्वारा मार दिया गया था। इन तस्वीरों को "राष्ट्र-विरोधी" माना गया और मसरत पर युवाओं को भड़काने और सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। मसरत ने हाल ही में कहा कि वह मामले की स्थिति से अनजान हैं क्योंकि उन्हें अब तक प्राथमिकी की कोई प्रति नहीं प्रदान नहीं की गई है।

नई दिल्ली, भारत में 7 सितंबर, 2017 को भारत की एक वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग, जिनकी पुलिस के अनुसार मंगलवार को उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी थी। रॉयटर्स/कैथल मैकनॉटन

अध्याय (III): सही साधन/उपाश्रय प्राप्त करना

पिछले अध्याय में विभिन्न प्रकार के कानूनों पर प्रकाश डाला गया है जिनका उपयोग पत्रकारों को आपराधिक कार्रवाइयों के लिए लक्षित करने के लिए किया जाता है। यदि आप खुद को किसी आपराधिक अपराध का आरोपी बना हुआ पाते हैं, जब आप बचाव के उचित साधन की प्रतीक्षा कर रहे हों तो आपके पास उचित उपाय खोजने और कुछ सुरक्षा पाने के अधिकार हैं। यह अध्याय इस बात पर चर्चा करेगा कि यदि आप अपने काम के दौरान आपराधिक आरोपों का सामना करते हैं तो आप कौन से कदम उठा सकते हैं।

एफआईआर क्या है?

- आपको केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब आपके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") के रूप में जानी जाने वाली पुलिस शिकायत दर्ज की गई हो।
- एक प्राथमिकी एक अपराध की घटना का वर्णन करने वाला एक बयान है, जिसे पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है जब उन्हें पहली बार इस तरह के आरोप के बारे में पता चलता है।
- यह पुलिस को अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और आरोप की जांच शुरू करने की अनुमति देता है।
- पुलिस केवल उन मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज कर सकती है जो 'संज्ञेय' अपराध से संबंधित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") उन अपराधों को निर्धारित करती है जिन्हें संज्ञेय माना जाता है और जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
- अगर आपके खिलाफ कोई गैर-संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस को गिरफ्तारी करने के लिए अदालत से वारंट जारी करवाना होगा।

यदि आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो आप क्या कर सकते हैं?

- आपको यह जानने का अधिकार है कि आप पर किन अपराधों का आरोप लगाया गया है और आप अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति देखने की मांग कर सकते हैं।
- गिरफ्तारी से पहले आप अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम जमानत यह सुनिश्चित कर सकती है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, भले ही आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हो।
- अपने वकील से संपर्क करें और उपयुक्त अदालत में इस आधार पर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें, कि आपके खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
- आपको अग्रिम जमानत देते समय कुछ नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा जो अदालत आप पर लगा सकती है। उदाहरण के लिए, आपको पुलिस द्वारा आपसे पूछताछ करने की अनुमति देने की आवश्यकता, देश छोड़कर नहीं जाना, आदि।
- जबकि एक अग्रिम ज़मानत आम तौर पर एक परीक्षण के अंत तक विस्तारित होती है, इसे एक अदालत द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

एफआईआर को कैसे रद्द किया जाए?

- रद्द करने का अर्थ केवल प्राथमिकी को निरस्त या रद्द कर देना होता है।
- अपने वकील से कहें कि वह आपके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने में मदद करे।
- अदालतें अभियुक्तों को केवल परेशान करने और बदनाम करने के लिए उन एफआईआर को रद्द कर देती हैं जो बिना किसी वास्तविक अपराध के दायर की गई प्रतीत होती हैं।
- आप इस उपाय की तलाश कर सकते हैं ताकि आपके खिलाफ मामला खत्म हो जाए और यह दिखाया जा सके कि आपको दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठे मामले में फंसाया गया है।

गिरफ्तार होने की स्थिति में: अधिकार एवं प्रतिवाद (विराम पत्र)

- **गिरफ़्तारी/जमानत के आधार जानने का अधिकार:**

गिरफ्तार होने पर, पुलिस अधिकारी को आपको आपकी गिरफ़्तारी के सभी विवरणों के बारे में सूचित करना चाहिए, जिसमें वो कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं जिनके तहत आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, और जहाँ वे लागू हो रहे हैं, वहां उस आधार पर ज़मानत पाने के आपके अधिकारों के बारे में भी आपको सूचना दी जानी चाहिये।

- **दोस्तों/रिश्तेदारों को सूचित करने का अधिकार:**

कानून में यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं कि आपके दोस्तों और परिवार को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाए और वे आपकी मदद कर सकें।

  - आपको गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह आपको सूचित करे कि आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी मित्र या रिश्तेदार को सूचित कर सकते हैं।
  - गिरफ्तारी करते समय, पुलिस अधिकारी को एक "गिरफ्तारी का ज्ञापन" तैयार करना चाहिए जिस पर आपके और आपके किसी रिश्तेदार/पड़ोसी के प्रतिहस्ताक्षर हों।
  - इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आपके द्वारा नामित व्यक्ति को आपके ठिकाने का विवरण प्रदान करना चाहिए और उसे रिकॉर्ड करना चाहिए।

- **आपके वकील की उपस्थिति का अधिकार:**

भारत का संविधान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील या अधिवक्ता से परामर्श करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। यदि गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तो आप पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने के हकदार हैं, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। इसलिए, जब पूछताछ की जाती है, पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, या गिरफ्तार किया जाता है, तो आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि आप अपने वकील को बुलाएं और उन्हें पुलिस के साथ बातचीत का नेतृत्व करने दें। गिरफ्तारी पर, पुलिस को सीआरपीसी के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार सहित आपके अधिकारों के बारे में आपको सूचित करना आवश्यक है। यदि आप ऐसी कानूनी सहायता का अनुरोध करते हैं, तो पुलिस को निकटतम संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण को सूचित करना होगा, जो आपके लिए एक वकील नियुक्त करता है।

- **आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार:**

यह आपका मौलिक अधिकार है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी पूछताछ के दौरान चुप रहने के अधिकार को शामिल करने के लिए इस अधिकार की पहचान की है, यदि आप मानते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर देने से आपको दोषी ठहराये जाने की उचित संभावना है।

- **वारंट/आईडी देखना:**

जब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा हो तो उसे नाम एवं टैग के साथ पहचाना जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का नियम वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत ऐसा करना है। आप पहचान प्रमाण और वारंट देखने के लिए कह सकते हैं (स्थिति के आकलन के अधीन)। ऐसे सीमित मामले होते हैं जब वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आगे के अपराध या सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जब एक संज्ञेय अपराध (जैसे कि एक पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्यों के दौरान बाधा डालना, आदि) किया जाता है। एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, आदि। बिना वारंट के गिरफ्तारी के कारणों को आमतौर पर लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

गिरफ्तारी के अलावा, किसी भी जानकारी के लिए तलाशी / जब्ती के लिए भी वारंट की आवश्यकता होती है। इसमें जांच के भाग के रूप में फोन या लैपटॉप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पुलिस की पहुंच होना शामिल है। ऐसे मामलों में, वारंट मांगना याद रखें और अगर आपको ऐसे किसी सबूत का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो अपने वकील से सलाह लें।

- **महिलाओं के अधिकार:**

यदि आप एक महिला हैं, तो आपको पुरुष अधिकारियों द्वारा केवल दिन के समय ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि आपको सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो वहां एक महिला पुलिस अधिकारी को उपस्थित होना होगा। गिरफ्तार किए जाने के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को छोड़कर आपको किसी के द्वारा छुआ नहीं जा सकता (जब तक कि आप गिरफ्तारी का विरोध नहीं करते)।

- **समय सीमा:**

अगर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

- **चिकित्सा का सहारा:**

यदि पुलिस हिरासत में आपको किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो आप एक चिकित्सकीय परीक्षण का आदेश देने के लिए अदालत से अनुरोध कर सकते हैं।

- **जमानत:**

अगर आपको जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो आपका वकील आपकी ओर से जमानत याचिका दायर कर सकता है। जमानती अपराध के मामले में, आप व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर सीधे पुलिस से जमानत प्राप्त कर सकते हैं और अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता है। आपका वकील व्यक्तिगत जमानत आवेदन दायर कर सकता है, क्या आपने एक बांड पर हस्ताक्षर किए हैं, और पुलिस से अपनी रिहाई की मांग कर सकते हैं।

कुछ मामलों में, जब आप पुलिस कार्रवाई का अनुमान लगा रहे हों, तो आप अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

- **चेतावनियां:**

किसी पुलिस अधिकारी के पूछे जाने पर अपना नाम और पता साझा करने से इंकार न करें क्योंकि यह गिरफ्तारी का एक आधार हो सकता है। हालाँकि, आपको इस आधार पर 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

पुलिस से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट करते समय या पुलिस के साथ बातचीत करते समय, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा बिना वारंट के गिरफ्तारी का आधार है। पुलिस के साथ किसी असहयोग को शामिल करने के लिए इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस देता है, तो यह सलाह दी जाती है कि आप उसका पालन करें (अपने वकील के साथ)। यदि आप पुलिस के साथ सहयोग करते हैं तो मजिस्ट्रेट जमानत देने के इच्छुक होते हैं।

यदि आपको 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाए?

- अगर पुलिस 24 घंटे के निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्तियों को पेश नहीं करती है, या सप्ताहांत के दौरान गिरफ्तारी करती है, या गिरफ्तारी रिकॉर्ड और दस्तावेज में बदलाव करती है, तो एक वकील सहायता के लिए अदालत से संपर्क कर सकते हैं और गलत ढंग से हिरासत में लिये जाने के रिकॉर्ड को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- अगर आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो आपके वकील बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसका मतलब अदालत से पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका है।
- ऐसी याचिका सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।
- न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया हो, या कोई अपराध किए बिना गिरफ्तार किया गया हो, या गलत इरादे से गिरफ्तार किया गया हो।
- अदालतें गिरफ़्तारी के आधार के बारे में भी सवाल पूछ सकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई अपराध नहीं बनता है, तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे सकती हैं।

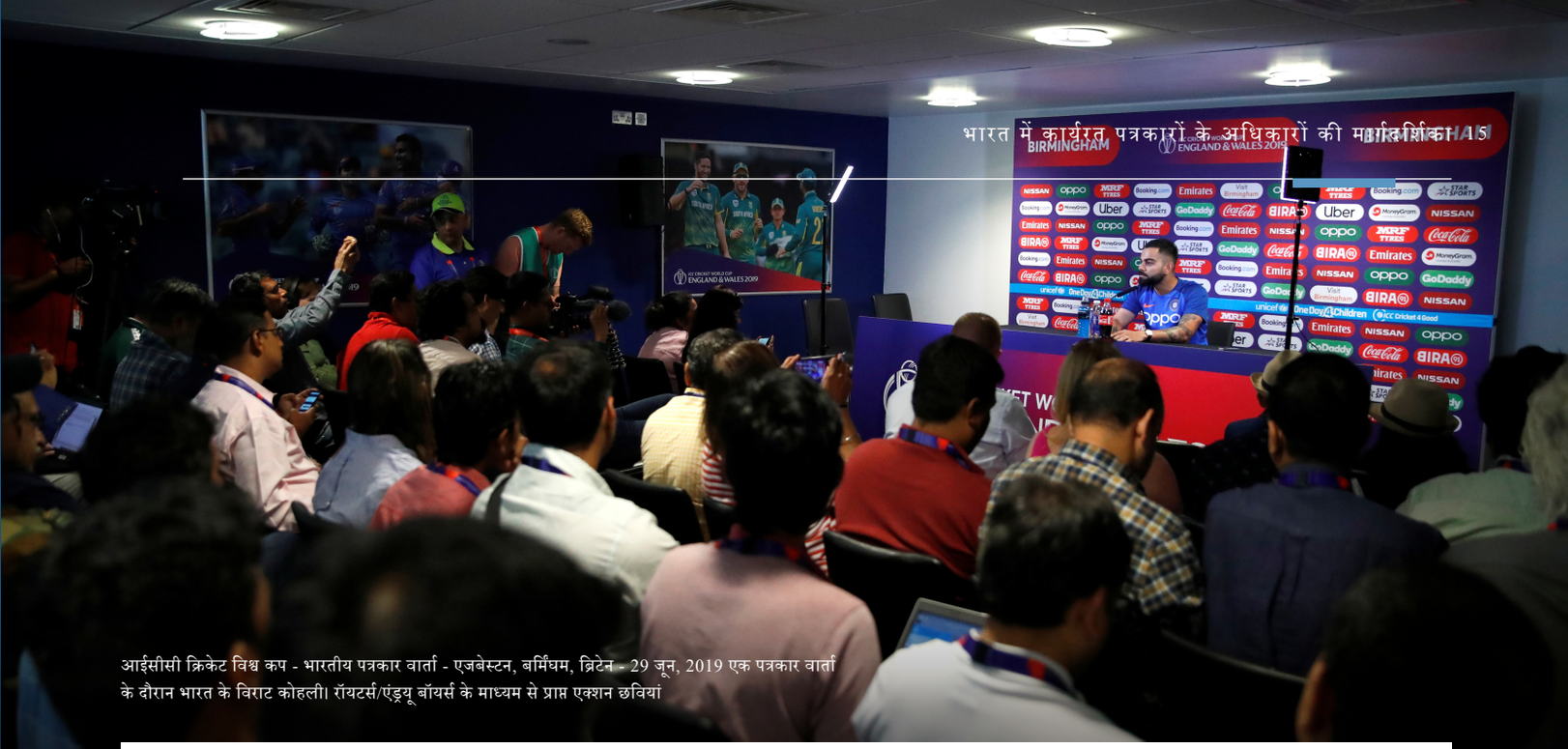

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप - भारतीय पत्रकार वार्ता - एजबेस्टन, बर्मिंघम, ब्रिटेन - 29 जून, 2019 एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारत के विराट कोहली। रॉयटर्स/एंड्रयू बॉयर्स के माध्यम से प्राप्त एक्शन छवियां

अध्याय (IV): अचानक कई मुकदमों में नामजद कर दिया जाना

आप खुद को उन स्थितियों में पा सकते हैं जहां आपके द्वारा प्रकाशित किसी भी रिपोर्टिंग या राय के लिए, आप पर मुकदमा चलाया जाता है। कानूनी मुकदमे के साथ-साथ, आपके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप हो भी सकता है और नहीं भी। कानूनी कार्रवाइयों के लिए नोटिस देना बड़े निगमों और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा पत्रकारों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। लंबी चलने वाली अदालती लड़ाइयों और अत्यधिक कानूनी फीस की संभावना का उपयोग पत्रकारों को उनके सार्वजनिक बयानों को वापस लेने और उनकी आवाज़ को शांत करने के लिए धमकाने के लिए किया जाता है। अक्सर जिन प्रकाशकों के प्रकाशनों ने आपका काम किया है, उन्हें भी इसी तरह के नोटिस दिए जाते हैं और आपके साथ मुकदमे में घसीटा जाता है। ऐसे मुकदमों को स्ट्रैटेजिक लीगल एक्शन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन (SLAPP) सूट कहा जाता है।

SLAPP सूट में शिकायतकर्ता आमतौर पर क्या मांग करते हैं?

- नुकसान, यानी, शिकायतकर्ताओं की प्रतिष्ठा को पहुंची चोट के लिए मुआवजे के रूप में पैसा;
- निषेधाज्ञा, यानी उस पत्रकारीय अंश के प्रकाशन पर रोक लगाने के आदेश जिसके खिलाफ शिकायत की गई है;
- यदि संबंधित अंश पहले ही प्रकाशित हो चुका है तो उसे वापस लेना;
- संबंधित पत्रकारीय अंश के लिए सार्वजनिक क्षमायाचना जारी करना;
- लेख में लिए गए रुख को स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक वक्तव्य जारी करना।

यदि आपको ऐसा नोटिस प्राप्त हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं?

पहचानें कि आप पर मुकदमा क्यों किया जा रहा है

- आप पर दीवानी मानहानि का मुकदमा किए जाने की सबसे अधिक संभावना है, जहां शिकायतकर्ता आपसे आपके बाईं ओर के बॉक्स में दिए गए किसी भी उपाय की मांग करेगा।
- आप पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाते हुए आपके विरुद्ध एक आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है। आपराधिक कार्यवाही के मामले में आपके पास जो उपाय है, उसके लिए कृपया Chapter IIऔर अध्याय (III) देखें।

कानूनी प्रतिनिधित्व की तलाश करें

- SLAPP सूट आपके अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला है और आपको इस तरह के अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ अपना बचाव करने का अधिकार है।
- अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की तलाश करें और आपको प्राप्त हुए नोटिस का जवाब देने में मदद करें।
- मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, यदि आप वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं तो कृपया अध्याय (III) देखें।
- याद रखें कि जनहित में किए गए सच्चे दावे कानून के तहत संरक्षित हैं।

निम्नलिखित केस अध्ययन SLAPP मुकदमों के खिलाफ सफल बचाव के उदाहरण हैं:

मेसर्स क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम राजस्थान पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड

यह एक स्थानीय समाचार प्रकाशन, राजस्थान पत्रिका, और उसके पत्रकारों के खिलाफ कीटनाशकों और कीटनाशकों के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उद्योग-निकाय द्वारा खेती में ऐसे रसायनों के उपयोग से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान पर चर्चा करने वाले लेखों को ले जाने के लिए दायर किया गया एक दीवानी मानहानि का मामला था। अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने के लिए SLAPP के मुकदमे के रूप में इस मुकदमे को खारिज कर दिया क्योंकि:

- लेखों में किसी व्यक्ति विशेष का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जा रहा था और इसलिए कोई मानहानि नहीं थी।
- मुक़दमे का प्रयास कीटनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग पर बहस को दबाना था।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एन्ड मैनेजमेंट बनाम मैसर्स दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन

यह कारवां पत्रिका के लेखक, संपादक, प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा था, जिसमें आईआईपीएम की कथित धोखाधड़ी प्रथाओं के बारे में कहानियां थीं। मामला खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रकाशक यह दिखा सकते थे कि:

- • उनके लेखों में किए गए दावे व्यापक शोध पर आधारित थे।
- • कारवां के पत्रकारों ने दुर्भावनावश ये कहानियाँ नहीं लिखीं।

प्रणजॉय गुहा ठाकुरता पर मानहानि का आरोप

इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली (EPW) के पूर्व संपादक, परंजय गुहा ठाकुरता और उनके सहयोगियों को एक कानूनी नोटिस मिला, जिसमें अडानी पावर लिमिटेड ने जून 2017 में प्रकाशित एक कहानी पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी पावर लिमिटेड को आर्थिक क्षेत्रों पर सरकार के बदले हुए नियमों से आर्थिक रूप से लाभ हुआ है। ईपीडब्ल्यू के बोर्ड समीक्षा ट्रस्ट ने ईपीडब्ल्यू से रिपोर्ट हटाने का फैसला किया। इसने संपादक के रूप में ठाकुरता के इस्तीफे को प्रेरित किया। बाद में, सेंसर किए गए लेख को द वायर ने फिर से प्रकाशित किया। इसने बाद अदानी समूह ने निषेधाज्ञा की मांग की। वर्ष 2019 में, अडानी ने ठाकुरता को छोड़कर वायर और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली। जनवरी 2021 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने ठाकुरता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मामला अभी भी चल रहा है, और ठाकुरता ने इस मामले की कार्यवाही को अहमदाबाद की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया की पत्नी जगिशा अरोड़ा, नई दिल्ली, भारत में 10 जून, 2019 को मीडिया सदस्यों के साथ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेती हुई।रॉयटर्स/अनुश्री फडणवीस

अध्याय (V): ऑनलाइन दुरुपयोग का मुकाबला करना

ऑनलाइन दुर्व्यवहार का मुकाबला करने के लिए पहला कदम यह समझना है कि आप इस तरह के उत्पीड़न का शिकार कब हो सकते हैं। फिर आप अपने नियंत्रण में उपचारों पर विचार कर सकते हैं - चाहे वह कानूनी सहारा लेने से संबंधित हो, या अन्य व्यावहारिक कार्रवाई। यह अध्याय उन पिछले उदाहरणों से सीख लेता है जहां पत्रकारों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है और ऐसे मामलों में किस प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन दुरुपयोग के प्रकार क्या हैं?	ऑनलाइन दुरुपयोग से कैसे निपटा गया है?
धमकियाँ आपको शारीरिक और शारीरिक नुकसान या चोट पहुंचाने वाले बयानों से निशाना बनाया जा सकता है। मौत की धमकी देना , शारीरिक या यौन हिंसा की धमकी देना, भेदभावपूर्ण टिप्पणियां करना, सोशल मीडिया पर विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ देखा जाता है।	भारतीय टेलीविजन पत्रकार बरखा दत्त को उनकी पत्रकारिता के लिए एक अज्ञात कॉलर से फोन पर बलात्कार, यौन शोषण और जान से मारने की धमकियां मिलीं। ऑनलाइन ट्रोल और गुमनाम कॉल करने वालों द्वारा और अधिक निशाना बनाए जाने पर, उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। इस मामले की जाँच दिल्ली साइबर क्राइम सेल द्वारा की गयी, साइबर क्राइम सेल ने अपराधियों की पहचान करने के साथ उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
डराना-धमकाना आपको डराने-धमकाने के उद्देश्य से डराने-धमकाने वाले व्यवहार करना जैसे कि पीछा करना, ट्रोलिंग करना, मानहानि आदि का ऑनलाइन इस्तेमाल करना। डराने-धमकाने का इस्तेमाल अक्सर पत्रकारों को उनके द्वारा किसी समाचार के सन्दर्भ में की जा रही जाँच-पड़ताल या पत्रकारिता (समाचार संकलन) को रोकने के लिए किया जा सकता है।	राणा अय्यूब, एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार को घृणास्पद वीडियो, ट्वीट्स और दुष्प्रचार अभियान के साथ ऑनलाइन लक्षित किया गया था। तब से, कई पत्रकार वकालत समूहों, प्रेस निकायों, और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार द्वारा उनके जीवन और सुरक्षा के खिलाफ कथित खतरों की जांच, दोषियों की पहचान करने और मुकदमा चलाने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी मांगते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया।
साइबरस्टॉकिंग साइबरस्टॉकिंग धमकी और डराने-धमकाने के साथ अधिव्यापित होता है। इसमें अवांछित संपर्क, स्पैमिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से बार-बार उत्पीड़न करना, अश्लीलता या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को पोस्ट करना शामिल है।	हैदराबाद में महिला पत्रकारों ने साइबर स्टाकिंग की अपनी कहानियों को साझा किया है और बताया है कि कैसे उन्हें अज्ञात व्यक्तियों से जानकारी मांगने या अवांछित प्रस्ताव वाले टेलीफोन कॉल और संदेश प्राप्त होते हैं। कुछ पत्रकार इस बात पर चर्चा करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को ब्लॉक करने से उन्हें कैसे मदद मिली, जबकि अन्य ने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना, क्योंकि वे सूचना के स्रोतों को खोना नहीं चाहते थे जो उनके कवरेज के लिए सहायक हो सकते हैं। एक उपाय जो पत्रकारों में से एक को प्रभावी लगा, वह उन्हें पुलिस कार्रवाई की धमकी देना था।

डॉक्सिंग यह ऑनलाइन संपर्क विवरण सहित व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत तरीके से लीक करने पर जोर देता है। डॉक्सिंग आम तौर पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की ओर ले जाता है जो इस तरह के जोखिम के कारण किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।	साकेत गोखले एवं एएनआर बनाम भारत संघ के खिलाफ एक पूर्व पत्रकार के संपर्क विवरण को उसके सूचना के अधिकार आवेदन से अनजाने में भारत सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया था। बाद में उन्हें गंभीर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया, जो लीक के लिए जिम्मेदार था, न्यायालय ने तीन महीने के भीतर जांच करने और सूचना लीक के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
ऑनलाइन प्रतिरूपण एक पत्रकार के रूप में, आप ऑनलाइन प्रतिरूपण के शिकार हो सकते हैं यदि आप किसी और के नाम के तहत एक ऑनलाइन उपस्थिति के संपर्क में आए हैं, आमतौर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति या सोशल मीडिया पर एक नकली खाते के माध्यम से।	वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान ऑनलाइन प्रतिरूपण का शिकार हो गईं, जब उन्हें जाली दस्तावेजों से जुड़े ईमेल की एक श्रृंखला के माध्यम से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक शिक्षण पद के लिए नौकरी का फर्जी प्रस्ताव मिला। उन्होंने अज्ञात उपयोगकर्ता के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी और प्रतिरूपण सहित संज्ञेय अपराधों के लिए पुलिस के पास इस मामले को साझा किया; और यह जांच अब भी चल रही है। इस मामले को न्यूयॉर्क टाइम्स में पत्रकारों द्वारा प्रकाशित खोजी समाचार रिपोर्ट के माध्यम से भी व्यापक कवरेज मिली।
ट्रोलिंग साइबर हमलों के सबसे आम रूपों में से एक, ट्रोलिंग में एक ऑनलाइन समुदाय में शत्रुतापूर्ण या आपत्तिजनक टिप्पणियों, संदेशों, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से घृणित हमले शामिल हैं।	हालांकि पत्रकारों के ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होने की ढेरों घटनाएं हुई हैं, कुछ उदाहरण सरकार की किसी आलोचना को लक्षित करने के एक संगठित प्रयास का हिस्सा हो सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के आईटी सेल के कर्मचारी होने का दावा करने वाले एक गुमनाम ट्विटर उपयोगकर्ता के आरोपों के आधार पर, द वायर की एक टीम ने इस मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि एक ऐप टेक फॉग का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया ऑपरेटिव द्वारा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर निष्क्रिय खातों को अपने हाथ में लेने इरादे से किया जा रहा था। ऐप की विशेषताओं ने उन्हें पार्टी की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ घृणित संदेश या सीधे ट्रोलिंग अभियान भेजने की अनुमति दी। एक प्रमुख पत्रकार निकाय, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने की मांग की और साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिये जाने की भी मांग की।

आप खुद को कुछ अन्य प्रकार के ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार भी पा सकते हैं जैसे:

- साइबर चोरी जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी की चोरी शामिल है
- आपकी सहमति से या उसके बिना ली गई अंतरंग या यौन छवियों का बदला लेने वाला अश्लील या गैर-सहमति वितरण
- आपको आपत्तिजनक सामग्री भेजना, जिसमें आपकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें या पोर्नोग्राफ़ी शामिल है
- मानहानि और दुष्प्रचार अभियान
- स्पैमिंग

ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ उपाश्रय (मदद) कैसे लें??

- स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करें- आप प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं (कृपया प्राथमिकी पर अधिक विवरण के लिए अध्याय (III) देखें)।

याद रखें, आपकी शिकायत दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है और यदि वे ऐसा करने से मना करते हैं, तो आप पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा लिखित शिकायत भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में, उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। यदि अधिकारी मददगार नहीं हैं या आपकी शिकायत को खारिज कर रहे हैं, तो अपने वकील से उन कानूनों के बारे में सलाह लें जो आपकी रक्षा कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कानून के आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्रावधानों की एक सूची है, जिस पर आप ऑनलाइन दुर्व्यवहार की घटनाओं के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते समय भरोसा कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

भारतीय दंड संहिता	
पीछा करना (धारा 354D)	किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी रूप के उपयोग के आधार पर किसी महिला की निगरानी करने वाले को पीछा करने का अपराध माना जाएगा।
आपराधिक धमकी (धारा 503)	आपराधिक धमकी में किसी व्यक्ति, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल है। यहां चोट का खतरा केवल आप तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके हित में किसी के लिए भी हो सकता है।
गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी (धारा 507)	गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपना नाम या निवास की जानकारी छुपाता है, एक दंडनीय अपराध है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	
अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा (धारा 67)	अश्लील सामग्री वाली कोई भी अन्तर्निहित वस्तु जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित हुई है (पढ़ने, देखने या सुनने के लिए) एक अपराध है।
इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा (धारा 67ए)	इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से किसी भी यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण भी दंडनीय है।

- **साइबर-क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल -** केंद्रीय जांच ब्यूरो के तहत स्थापित और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में, इन निकायों के पास आईटी अधिनियम के तहत अपराधों और प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य अपराधों की जांच करने की शक्ति है। साइबर अपराधों से संबंधित स्थानीय पुलिस को की गई शिकायतें आम तौर पर संबंधित साइबर-अपराध प्रकोष्ठ को अग्रेषित की जाती हैं। आप अपनी ऑनलाइन उत्पीड़न संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करना छोड़ सकते हैं और सीधे साइबर क्राइम सेल से संपर्क कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम सेल को लिख सकते हैं, घटना का विवरण दे सकते हैं और प्रासंगिक जानकारी के साथ-साथ अपनी संपर्क जानकारी भी संलग्न कर सकते हैं। दिल्ली में, साइबर-अपराध की घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक विशेष वेबसाइट, http://www.cybercelldelhi.in/ शुरू की गई है, जो विभिन्न साइबर अपराधों की जानकारी भी प्रदान करती है।

- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल -** यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा की गयी एक पहल है, जो साइबर-अपराधों से संबंधित शिकायतों को https://cybercrime.gov.in/ पर ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देता है।

- **बिचौलियों के शिकायत अधिकारी से शिकायत करना -** कानून को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों और एप्लिकेशन जैसे ऑनलाइन बिचौलियों की आवश्यकता होती है, जो सामुदायिक दिशानिर्देशों का एक संग्रह बनाते हैं और प्रकाशित करते हैं जो अनुमेय और निषिद्ध सामग्री की श्रेणियों की व्याख्या करते हैं जो वे पोस्ट कर सकते हैं। बिचौलियों को एक शिकायत अधिकारी की संपर्क जानकारी नियुक्त करने और प्रकाशित करने की भी आवश्यकता होती है जो उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को स्वीकार करता है और उनका समाधान करता है। यदि आपके साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप शिकायत अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं और परेशान करने वाली सामग्री को हटाने या ऐसी सामग्री पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- **पीयर-टू-पीयर समर्थन -** ऑनलाइन साथी पत्रकारों के समर्थन को इकट्ठा करना न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों से किसी भी संभावित प्रतिक्रिया को तेज करने की एक प्रभावी रणनीति है, बल्कि यह जागरूकता भी फैलाती है और समान स्थिति में उन लोगों के लिए एक समर्थन केंद्र बनाती है। पत्रकार राणा अय्यूब के मामले में कोयलेशन अगेन्स्ट ऑनलाइन वॉयलेंस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, संयुक्त राष्ट्र जैसे निकाय पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने में

कामयाब रहे हैं। साथ ही यह पत्रकारों के लिए डिजिटल युग के इन मुद्दों में छात्रवृत्ति और भागीदारी को भी प्रेरित करता है; अनुसंधान अध्ययनों में आगे बढ़ने से साक्ष्य स्थापित करने में मदद मिलती है जिसका उपयोग पत्रकारों की सुरक्षा में और क्रांति लाने के लिए किया जा सकता है।

पत्रकारों का ऑनलाइन दुरुपयोग एक राष्ट्रीय और वैश्विक चिंता का विषय है। प्रासंगिक जानकारी के साथ पत्रकारों को सशक्त बनाने के लिए निर्मित की गयी विभिन्न मार्गदर्शिकाओं में आपको राहत मिल सकती है:

- ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाव के लिए संसाधनों पर सीपीजे की जानकारी।
- अंतरराष्ट्रीय समाचार सुरक्षा संस्थान, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और यूनेस्को के पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन हमले: अपने अधिकारों को जानें मार्गदर्शिका।
- आईएफजे की बाइट बैक: दक्षिण एशिया में साइबर उत्पीड़न से निपटने के लिए पत्रकारों की मार्गदर्शिका।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' पत्रकारों का ऑनलाइन उत्पीड़न: ट्रोल्स का हमला।
- अपने ट्रोल्स या ऑनलाइन विरोधियों के साथ बातचीत करना हमेशा उचित नहीं होता है; लेकिन यदि आप ऐसा करना चुनते हैं, तो आप काउंटर-स्पीच के सुरक्षित अभ्यास के लिए पेन अमेरिका के दिशानिर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं।

18 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय परिसर के अंदर अपना कैमरा सेट करते हुए एक टेलीविजन पत्रकार। रॉयटर्स/अनिंदितो मुखर्जी

अध्याय (VI): कोविड 19 (COVID-19) से संबंधित पत्रकारिता

भारत ने कोविड -19 (COVID-19) महामारी से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी देखा है। भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी सलाह, दिशा-निर्देशों और आदेशों के आधार पर, यह अध्याय COVID-19 महामारी पर रिपोर्टिंग के लिए कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। कृपया ध्यान दें कि इस संबंध में कानूनी स्थिति विकसित हो रही है और नीचे दिया गया मार्गदर्शन 7 अक्टूबर 2022 तक की कानूनी स्थिति पर आधारित है।

सामान्य दिशानिर्देश:

- महामारी के बारे में जानकारी के लिए प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। ऐसे कई सरकारी बुलेटिन हैं जो कोरोनावायरस के मामलों और मौतों की दैनिक संख्या की रिपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में एक फैसले में ऐसे स्रोतों को रिपोर्टिंग के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया है, हालांकि पत्रकारों को अन्य आधिकारिक स्रोतों का उल्लेख करने से रोकने के लिए कोई ठोस प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- महामारी पर अपनी रिपोर्ट में सत्यापित स्रोतों को शामिल करें। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली गैर-पारंपरिक/असत्यापित जानकारी को बढ़ावा देना महामारी रोग अधिनियम ("ईडीए"), आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय हो सकता है। ऐसे समाचार पोस्ट न करें जो "झूठा अलार्म" हो सकता है और "आतंक" पैदा कर सकता है क्योंकि यह डीएमए के तहत अपराध है।
- ध्यान दें कि सरकार को व्यापक अधिकार देने वाले ईडीए के तहत फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में गिरफ्तारियां की गई हैं।
- ऑनलाइन समाचार मीडिया संस्थानों को गलत सूचना के बारे में जागरूकता शुरू करनी चाहिए और अपने प्लेटफॉर्म से कोरोनावायरस से संबंधित किसी भी गलत सूचना को हटाना/अक्षम करना चाहिए। पत्रकारों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया घरानों का प्रबंधन जिम्मेदार है।
- आपको कुछ विशिष्ट राज्य-विशिष्ट कानूनों के अनुसार कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली जैसे राज्यों को किसी भी संगठन/संस्था/व्यक्ति को COVID-19 की जानकारी के लिए किसी भी प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी पत्रकारों के लिए कोविड रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देशों के विशिष्ट संग्रह जारी किए हैं, जैसे कि

- स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के लिए COVID-19 पर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए यूनिसेफ के सुरक्षा दिशानिर्देश,
- पत्रकारों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की COVID-19 जानकारीपूर्ण गाइड जिसमें महामारी से संबंधित जानकारी की रिपोर्टिंग के निर्देश हैं, और
- सीपीजे सुरक्षा परामर्शिका : क्षेत्र में सुरक्षित रहने की जानकारी के साथ कोरोना वायरस महामारी को कवर करना।

चल रही महामारी से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए आप इन संसाधनों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

हमारे बारे में

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। हम सुरक्षित रूप से और प्रतिशोध के डर के बिना समाचार रिपोर्ट करने के पत्रकारों के अधिकार की रक्षा करते हैं। हर साल सैकड़ों पत्रकारों पर हमला किया जाता है, उन्हें कैद किया जाता है या मार दिया जाता है। 40 से अधिक वर्षों से, सीपीजे उनका बचाव करने और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए वहाँ मौजूद है। दुनिया भर के 50 से अधिक विशेषज्ञों की एक टीम के साथ, सीपीजे दस्तावेजीकरण करने के साथ प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा करता है, राज्य के प्रमुखों और उच्च-श्रेणी के अधिकारियों के साथ बैठक करता है, राजनयिक प्रयासों पर नेतृत्व करता है या सलाह देता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य संगठनों के साथ काम करता है कि जब भी पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है तोँ उन मामलों में न्याय हो। सीपीजे दुनिया भर के पत्रकारों को अद्यतन सुरक्षा जानकारी और तीव्र प्रतिक्रिया सहायता के माध्यम से व्यापक, जीवन रक्षक सहायता भी प्रदान करता है। सीपीजे के बारे में अधिक जानकारी और पत्रकारों को उपलब्ध सहायता के लिए कृपया http://www.cpj.org/ पर जाएं

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी, भारत की लब्ध-प्रतिष्ठित पूर्ण-सेवा प्रदान करने वाली कानून फर्मों में से एक है, जो गत एक शताब्दी से उत्कृष्टता की एक मिसाल है। भारत की प्रमुख कानून फर्मों में से एक के रूप में, वे अपने ग्राहकों को बढ़ने, नया करने और फलने-फूलने में मदद करते हैं। फर्म ने अपनी विशेषज्ञता, विशेष समाधान और आगे सोचने की क्षमता के लिए प्रतिष्ठा बनाई है। वे अपने ग्राहकों की समग्र कानूनी चुनौतियों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और उच्च अनुरूप समाधान ढूंढते हैं।

थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन

थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन मीडिया की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने, अधिक समावेशी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। समाचार, मीडिया विकास, मुफ्त कानूनी सहायता और आयोजन पहलों के माध्यम से, यह फाउंडेशन प्रणालीगत परिवर्तन को चलाने के लिए अपनी अनूठी सेवाओं को जोड़ता है। ट्रस्टलॉ, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक पहल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा निशुल्क कानूनी नेटवर्क है। प्रमुख कानून फर्मों और कॉर्पोरेट कानूनी टीमों के साथ काम करते हुए, हम 175 देशों में गैर-लाभकारी संस्थाओं और सामाजिक उद्यमों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, अभूतपूर्व कानूनी अनुसंधान और संसाधनों की सुविधा प्रदान करते हैं। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, ट्रस्टलॉ (Trust Law) यह सुनिश्चित करना चाहता है कि गैर-लाभकारी और सामाजिक उद्यमों के पास वे उत्तर हों जिनकी उन्हें जोखिमों को कम करने और अपने संगठनों को चालू रखने के लिए आवश्यकता है। यदि आपके पास संसाधनों के लिए विचार हैं तो हम उन्हें विकसित कर सकते हैं या आपके पास कानूनी अनुसंधान परियोजनाएं हैं जो इस मार्गदर्शिका को पढ़ने के बाद सहायक होंगी, कृपया हमसे संपर्क करें। यदि आप एक गैर-लाभकारी या सामाजिक उद्यम हैं, जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो आप यहां सेवा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निःशुल्क ट्रस्टलॉ में शामिल हो सकते हैं।

आभार और अस्वीकरण

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन शार्दुल अमरचंद एंड कंपनी की कानूनी टीम द्वारा मिले सहयोग को स्वीकार करना और उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को संभव बनाने के लिए नि: स्वार्थ आधार पर अपने समय और विशेषज्ञता का योगदान दिया।

यह रिपोर्ट केवल सूचना उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है। यह कानूनी सलाह नहीं है। पाठकों से आग्रह है कि वे अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के संबंध में योग्य कानूनी परामर्शदाता से सलाह लें।

हम प्रकाशन के समय तक इस रिपोर्ट में लिखित सामग्री को सही और अद्यतित होने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम उनकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देते हैं, विशेष रूप से प्रकाशन के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, इस रिपोर्ट पर निर्भरता या इसमें किसी भी अशुद्धियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्रवाई या किए गए कार्यों या किसी भी नुकसान के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी ने उदारतापूर्वक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स को निशुल्क अनुसंधान प्रदान किया है। हालांकि, इस रिपोर्ट की सामग्री को शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी या योगदान देने वाले वकीलों के विचारों या विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।

इसी तरह, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन इस रिपोर्ट पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारी ट्रस्ट लॉ सदस्य समिति का समर्थन करने पर गर्व महसूस कर रहा है, जिसमें प्रकाशन और कानूनी शोध को संभव बनाने वाले निशुल्क संबंध शामिल हैं। हालांकि, स्वतंत्रता और पूर्वाग्रह से मुक्ति के थॉमसन रॉयटर्स ट्रस्ट सिद्धांतों के अनुसार, हम इस रिपोर्ट की सामग्री, या इसमें व्यक्त किए गए विचारों पर कोई स्थिति निर्धारण नहीं करते हैं।

To access the Know Your Rights Guide for Journalists in India, please visit the Resources section on https://www.trust.org/trustlaw/ and https://cpj.org/

13 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में भारतीय संसद के परिसर से पत्रकारिता करते हुए टेलीविजन पत्रकार।
रॉयटर्स/अदनान आबिदी

THOMSON REUTERS FOUNDATION | TrustLaw | CPJ Committee to Protect Journalists | Shardul Amarchand Mangaldas